[श्री मोती भाई आर० चौधरी]

गया है कि अगर यह ट्रेनें 15 दिन में चालू नहीं करदी जायेंगी तो सत्याग्रह करने में आयेगा। अतः मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि इस विभाग में बहुत लम्बे समय से नीचे की जो दो ट्रेनें बन्द हैं, उनको जल्दी से चालू करवा दिया जाए, जिससे विद्यार्थियों, मजदूरों और कर्मचारियों को राहत हो। ये दो ट्रेनें नीचे के मुताबिक हैं :—

1. अहमदाबाद पाटण के बीच चलने वाली 120 डाउन गाड़ी।

2. 115–16 अप-डाउन गाड़ी जो अहमदाबाद पाटण के बीच वाया रगुज, चानसमा, बहुचराजी, कटोशन, कडी और कलोहल हो कर जाती है।

उपर्युक्त दो ट्रेनों को जल्दी से चालू करके हर रोज के यात्रियों को सुविधा दें और इस तरह से अपनी बढ़ती हुई रेल मूव में टकी प्रतीती करायें।

(viii) NEED TO RE-EMPLOY PUBLIC HEALTH VISITORS OF BIHAR WHOSE SERVICES WERE DISCONTINUED FROM 1ST SEPTEMBER, 1980.

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का आपके द्वारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 2 अक्तूबर, 1977 से देश भर में चालू "जनस्वास्थ्य रक्षक" योजना को 1 सितम्बर, 1980 से बिहार में समाप्त कर दिया गया है।

पूर्वांचल राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने कलकत्ते में बैठक लेकर एक प्रस्ताव पारित किया कि यह योजना जोरदार ढंग से चालू की जाए और अभी तक चलाया जा रहा है। यह योजना जनहित में बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई है।

बिहार में 7 हजार जन-स्वास्थ्य रक्षकों की सेवाएं समाप्त होने से नियोजित युवकों में भारी आक्रोश पैदा हो रहा है। बिहार में बेरोजगारियां सब से अधिक हैं और सरकार राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम की घोषणा कर नियोजित युवकों को बेकारी ग्रस्त करने की अजीब स्थिति पैदा कर रही है। यह केवल बिहार में हुआ है जो सौतेला व्यवहार कहा जा सकता है।

अतः भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय इस दिशा में समानता के आधार पर अन्य राज्यों में कार्यरत जन-स्वास्थ्य रक्षकों की तरह बिहार में भी सात हजार नवयुवकों को जन-स्वास्थ्य रक्षक की सेवा में पुनः नियोजित करे तथा उन्हें न्याय प्रदान करे।

(ix) NEED TO START THE PROPOSED KISAN SAHKARI CHINI MILL, LTD., MEHMOODABAD IN SITAPUR DISTRICT OF U.P.

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से नियम 377 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को उठाना चाहता हूं।

26–3–74 को किसान सहकारी चीनी मिल लि० महमूदाबाद जिला सीमापुर, उत्तर-प्रदेश की निर्माण योजना स्वीकृत हुई। इस मिल के निर्माण हेतु कुल चौरासी एकड़ भूमि क्रय में 5.07 लाख रुपया व्यय किया जा चुका है। किसानों के विभिन्न समुदायों व संस्थाओं ने लगभग 22 लाख रुपया अंश पूंजी भी जमा किया है। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए 90 लाख रुपये का अंशदान दिया था।

जब से इस मिल के बनने की बातचीत चली है क्षेत्र की जनता किसान मजदूर आशा लगाये हैं। छः साल से अधिक समय बीत गया है लेकिन केवल उद्घाटन का पत्थर ही लग सका है।